मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 1: वैकल्पिक देखरेख से परिचय

समय: 11:04

किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैकल्पिक देखरेख

किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के लिए गैर–संस्थागत और संस्थागत वैकल्पिक देखरेख दोनों का प्रावधान करता है। गैर संस्थागत वैकल्पिक देखरेख में दत्तक ग्रहण, पालक देखरेख , प्रायोजन और पश्चात्वर्ती देखरेख शामिल हैं। संस्थागत देखभाल में बाल देखरेख संस्थान जैसे बाल गृह, मुक्त आश्रय गृह , विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण , उचित सुविधा, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थान शामिल हैं।

आइए पहले गैर–संस्थागत वैकल्पिक देखरेख के बारे में जाने।

दत्तक ग्रहण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोद लिया हुआ बच्चा अपने जैविक माता–पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ, जो एक जैविक बच्चे से जुड़ी होती हैं, अपने दत्तक माता–पिता का वैध बच्चा बन जाता है।

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (57) के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण राज्य सरकार या स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा स्थापित गोद लेने के उद्देश्य से अनाथ, परित्यक्त और समर्पित किये बच्चों के आवास के लिए अधिनियम की धारा 65 के तहत मान्यता प्राप्त संस्था है।

विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन और जिला बाल संरक्षण इकाई के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

आइए हम विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें

- प्रत्येक बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी लेना , उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना य भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरा करनाय शैक्षिक और प्रशिक्षण की जरूरत पूरा करना य अवकाश और मनोरंजक गतिविधियाँ करना य किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से सुरक्षाय सामाजिक मुख्यधारा में जोड़ना
- अनाथ, परित्यक्त और समर्पित किये बच्चों का पंजीकरण
- सीडब्ल्यूसी को बच्चे के आगमन की सूचना देना
- भर्ती किए गए सभी बच्चों और भावी दत्तक माता–पिता का ऑनलाइन डेटाबेस बनाए रखना
- बाल अध्ययन रिपोर्ट और शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना
- बच्चों और भावी दत्तक माता–पिता को गोद लेने से पहले और बाद में परामर्श देना

• भावी दत्तक माता–पिता का पंजीकरण
• भावी दत्तक माता–पिता के साथ बच्चे का मिलान
• गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना
• बच्चे को गोद लेने से पहले पालक देखभाल में रखने की सुविधा प्रदान करना
• गोद लेने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करना

पालक देखरेख

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (29) के अनुसार पालक देखरेख से तात्पर्य है बच्चे को पारिवारिक वातावरण में वैकल्पिक देखरेख के उद्देश्य से रखना।

पालक देखभाल के लिए मॉडल दिशानिर्देश, 2016

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने परिवार की देखभाल से वंचित या ऐसा होने का खतरा होने वाले बच्चों की रक्षा करने के उद्देश्य से 2016 में पालक देखरेख के लिए मॉडल दिशानिर्देश लॉन्च किए। दिशानिर्देशों की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

परिवार या समूह पालक देखरेख में बच्चे का स्थानन

परिवार के पालक देखरेख में या एक उपयुक्त सुविधा में समूह पालक देखरेख में बच्चे के स्थानन की उपयुक्तता सीडब्ल्यूसी द्वारा निर्धारित की जा सकती है। निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले कुछ बिंदु निम्नवत हैं • बच्चे द्वारा अनुभव किए गए आघात का स्तर, • नशे की लत का इतिहास, • विकलांगता का स्तर और प्रकार, • सामाजिक व्यवहार, • किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता, लाइलाज बीमारी आदि • बच्चे का संस्थानीकरण होने से रोकना • सुविधाओं की उपलब्धता पप. बच्चे, या माता–पिता या अभिभावकों की वरीयता और सहमति, . विकल्प की उपलब्धता . विकल्प की उपयुक्तता

पालक देखरेख के लिए पात्र बच्चे

1. ऐसे बच्चे जिन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद भी गोद नहीं लिया जा रहा है। इसमे शामिल हैरू
• गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दो साल की अवधि के भीतर 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे जिन्हें या तो देश में गोद लेने या विदेश में गोद लेने वाला परिवार नहीं मिलता है
• 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, जो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक वर्ष के लिए किसी भी संभावित दत्तक माता–पिता द्वारा नहीं चुने गए हैं
• विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जिन्हें गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर या तो देश में गोद लेने या विदेश में गोद लेने वाला परिवार नहीं मिलता है
2. बच्चों को सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित नहीं किया गया

3. बच्चे जिन्हें संस्था से हटाकर ग्रुप फोस्टर केयर में रखा जा सकता है। इनमें संस्थानों में रहने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके माता–पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध किया है।

पालक परिवार की जिम्मेदारियां

मॉडल दिशानिर्देशों में उल्लेखित पालक परिवारों की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं

• पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना • बच्चे के संपूर्ण शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखभाल, सहायता और उपचार प्रदान करना • बच्चे की उम्र, विकासात्मक जरूरतों और रुचियों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना • शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करना

• घर और स्कूल के साथ तालमेल बिठाने में बच्चे की प्रगति से संबंधित जानकारी समय–समय पर सीडब्ल्यूसी और बच्चे के जैविक परिवार के साथ साझा करना और चर्चा करना, • घर के दौरे के दौरान बच्चे और डीसीपीयू कर्मचारियों के बीच संपर्क स्थापित करना

प्रायोजन

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (58) के अंतर्गत प्रायोजन का तात्पर्य है – बच्चे की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता का प्रावधान

प्रायोजन के प्रकार

निवारक प्रायोजनः
बच्चे को परिवार में बने रहने, उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए परिवार को सहायता प्रदान करना । यह बच्चों को निराश्रित, असुरक्षित होने, भाग जाने, बाल विवाह के लिए मजबूर करने, बाल मजदूरी करने आदि से रोकने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है। परिवारों या बच्चों को प्रायोजन सहायता के लिए डीसीपीयू अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं, आउटरीच कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के साथ–साथ ग्राम बाल संरक्षण समितियों की सहायता से पहचान करता है।

पुनर्वास के लिए प्रायोजनः ब के बच्चों को भी प्रायोजन सहायता से परिवारों में बहाल किया जा सकता है। व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर, एक संस्था सीडब्ल्यूसी/जेजेबी से संपर्क कर सकती है ताकि प्रायोजन निधि के माध्यम से पुनर्वास के लिए डीसीपीयू को उपयुक्त मामले की सिफारिश की जा सके। स्पॉन्सरशिप फंड की मंजूरी के लिए डीसीपीयू को सिफारिश करने से पहले सीडब्ल्यूसी/जेजेबी द्वारा मामलों की समीक्षा की जाती है।

वृहत परिवार में नातेदारों द्वारा देखरेख

इसका तात्पर्य बच्चे के वृहत या संयुक्त परिवार में परिवार आधारित देखभाल से है।

जिन बच्चों का परिवार नहीं है या जिनके परिवार उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें संयुक्तध्वृहत परिवार के सदस्यों द्वारा देखभाल प्रदान की जा सकती है। यदि कोई नातेदार उपलब्ध नहीं है या बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चे को एक इच्छुक परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के साथ सांस्कृतिक या सामुदायिक संबंध साझा करते है।
यदि ऐसी गैर औपचारिक देखरेख के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो इसे प्रायोजन कार्यक्रम के तहत माना जा सकता है जैसा कि अधिनियम या राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया है।

पश्चात्वर्ती देखरेख

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पश्चात्वर्ती देखरेख से तात्पर्य है उन व्यक्तियों के लिए वित्तीय या अन्य सहायता का प्रावधान करना, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन इक्कीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं, और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संस्थागत देखरेख से बाहर आ गए हैं ।

पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं

- छह से आठ व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक समूह आवास
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वजीफे का प्रावधान या उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और व्यक्ति को रोजगार मिलने तक सहायता
- राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और ऐसे अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति की व्यवस्था
- ऐसे व्यक्तियों के साथ उनकी पुनर्वास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए नियमित संपर्क में रहने के लिए एक परामर्शदाता का प्रावधान
- उद्यमशील गतिविधियों को स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था